जीबीसी के लिए पांच लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव तैयार : नन्दी

दस लाख करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्ताव आने की संभावना

- औद्योगिक विकास मंत्री ने की नवंबर में प्रस्तावित जीबीसी की तैयारियों की समीक्षा
- 4,33,528 करोड़ की आठ हजार परियोजनाएं हुई शुरू
- अधिकारियों को प्रस्ताव व निवेश की राशि बढ़ाने के निर्देश

नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी (फाइल)

राब्यू, जागरण• लखनऊ: नवंबर माह में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी 5.0) को लेकर विभिन्न कंपनियों ने इन्वेस्ट यूपी को पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों को प्रस्तावों की संख्या और निवेश की राशि बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जीबीसी में दस लाख करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्ताव आने की संभावना है। इसी के मद्देनजर विभिन्न विभागों के साथ तालमेल बनाकर प्रस्ताव तैयार किए जाएं।

सोमवार को पिकप भवन में उन्होंने जीबीसी की तैयारियों की समीक्षा की। कहा कि उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने वाला राज्य बनाने के हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने विभिन्न जिलों में तैनात उद्यमी मित्रों के नेटवर्क के कार्य संचालन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए तैयार किए गए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का उद्घाटन किया। कहा कि निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्मिकों की आवश्यकता है। इसके लिए कार्मिक कैडर रिव्यू किया जाए। प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को तैनात किया जाए और प्रतिष्ठित संस्थानों के युवाओं को अपने साथ जोड़ा जाए।

जीबीसी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति

- अभी तक हुई चार जीबीसी में 12,10,274 करोड़ रुपये की 16,478 परियोजनाएं शामिल हुई हैं।
- 4,33,528 करोड़ रुपये की 8,363 परियोजनाओं का वाणिज्यिक संचालन शुरू हो गया है।
- 7,76,746 करोड़ रुपये की 8,115 परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं।
- जिला स्तर पर 19,523 एमओयू उद्यमी मित्रों एवं जीएम डीआइसी के मध्य वितरित किए गए हैं।

इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनन्द ने बताया कि दो लाख करोड़ रुपये का निवेश करने वाली 62 कंपनियों को हाल ही में लेटर आफ कंफर्ट (एलओसी) दिया गया है। हर महीने 10 कंपनियों को एलओसी जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। 371 कंपनियां चीन से आना चाहती हैं, जिनसे संपर्क किया जा रहा है। फार्च्यून 500 इंडिया व फार्च्यून नेक्स्ट 500 इंडिया की सूची में शामिल 814 कंपनियां अकाउंट मैनेजरों को आवंटित की गई हैं। इस वर्ष लाजिस्टिक्स और औद्योगिक अवस्थापना विकास के लिए 1,400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग को भेजा गया है।